भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 842

दिनांक 6 फरवरी 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारत और चीन के बीच बढ़ता व्यापार घाटा

842 **डा. सैयद नसीर हुसैन:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारत का चीन को निर्यात वर्ष 2020-21 में 21.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वर्ष 2024-25 में 14.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबकि इसी अवधि में चीन से आयात 65.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 113.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगभग 99.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो किसी भी देश के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापार घाटा है; और

(ग) चीनी आयात पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से बार-बार की गई नीतिगत घोषणाओं के बावजूद, इस व्यापार घाटे में निरंतर वृद्धि होने के क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर) में चीन को भारत के निर्यात में वित्त वर्ष 2024-25 की इसी अवधि की तुलना में 36.68% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक भारत से चीन को निर्यात और भारत का चीन से आयात का विवरण वाणिज्य विभाग की वेबसाइट https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/country_wise_ttrade से प्राप्त किया जा सकता है।

वर्ष 2004-05 से वर्ष 2013-14 के दौरान भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 42.65 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा, जबकि वर्ष 2014-15 से वर्ष 2024-25 के

दौरान यह घटकर 7.42 प्रतिशत की सीएजीआर पर आ गया है, जो स्पष्ट रूप से चीन के साथ व्यापार घाटे के आयात वृद्धि की दर को नियंत्रित करने में सरकार की सफलता को दर्शाता है।

वैश्वीकरण के इस युग में, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ-साथ विकास के अवसरों को निर्धारित करने में तेजी से प्रभावशाली हो गई हैं। चूंकि भारत तेजी से वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हो रहा है, इसलिए सफल जीवीसी एकीकरण के लिए निर्यात जितना ही आयात भी महत्वपूर्ण हो गया है।

चीन से आयातित अधिकांश वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और कच्ची सामग्रियां, जैसे सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और असेंबलीज, मोबाइल फोन पार्ट्स आदि हैं, जिनका उपयोग तैयार उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है और जिन्हें भारत से निर्यात भी किया जाता है। इन वस्तुओं का आयात भारत में तेजी से बढ़ रहे क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेलीकॉम और विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और पेरिफेरल्स, टेलीफोन कंपोनेंट्स आदि के आयात में वृद्धि का श्रेय भारत के डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञानयुक्त अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को दिया जा सकता है।

घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। भारत के विनिर्माण क्षेत्र को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए दिनांक 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की गई। वर्तमान में, 'मेक इन इंडिया' 2.0 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों में क्रियान्वित 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारत के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, व्हाइट गुड्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों, उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल आदि जैसे 14 प्रमुख क्षेत्रों में 1.97 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की हैं, जहां आयात पर काफी निर्भरता है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास के लिए, सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है।

'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' के तहत कई पहलें की गई हैं, जिनमें बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी), बी-रेडी असेसमेंट, जन विश्वास और व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन के बोझ को कम करना शामिल है।

देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और पीएम गति शक्ति शुरू की गई है। पीएम गति शक्ति लोगों और

वस्तुओं की सुगम आवाजाही के लिए बहुआयामी अवसंरचना के एकीकृत विकास में भी सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र बनाना है।

सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों से कई क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता में भी कमी आई है। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन का आयात वर्ष 2014-15 में 48,609 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2024-25 में 3,710 करोड़ रुपये हो गया है। दूसरी ओर, मोबाइल फोन का निर्यात वर्ष 2014-15 में 1,566 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 2,05,017 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में कई क्षेत्रों में चीन से आयात में गिरावट देखी गई। उदाहरण के लिए, उर्वरकों (61.4%) के आयात में भारी गिरावट आई, इसके साथ ही अवशिष्ट रसायन और संबद्ध उत्पादों (19.7%), लोहा और इस्पात (10.3%), और कृत्रिम धागे (9.5%) में गिरावट आई।

सरकार भारतीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि आपूर्ति के एकल स्रोतों पर निर्भरता कम हो सके। इसके साथ ही, सरकार नियमित रूप से आयात में होने वाली वृद्धि की निगरानी करती है और उचित कार्रवाई करती है। इसके अलावा, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) को अनुचित व्यापार परिपाटियों के विरुद्ध व्यापारिक उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करने और उसकी सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है।

सरकार घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

******